

वेणुगोपाल हरियाणा में नई जाट "लीडरशिप" पनपाना चाहते हैं

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर, इस पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। हरियाणा कांग्रेस टकराव की ओर बढ़ रही है। पुराने जाट नेतृत्व की जगह नया नेतृत्व लाने की लड़ाई शुरू हो गई है। राज्य में हाल ही में हुये विधानसभा चुनावों में जीतकर आये 37 विधायकों में से 30 विधायक हरियाणा के सी.एल.पी. नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही, पार्टी के 5 निर्वाचित लोकसभा सांसदों में से 4 सांसद हुड्डा के साथ हैं। इनमें हुड्डा के पुत्र दीपेन्द्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं।

समझा जाता है कि के.सी. वेणुगोपाल नये जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पी.सी.सी. अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि सी.एल.पी. नेता का पद किसी गैर-जाट नेता को मिलेगा।

इस बदलाव के पीछे वेणुगोपाल के दो उद्देश्य हैं। पहली बात तो यह है कि वे हरियाणा में नया नेतृत्व चाहते हैं तथा

■ स्वाभाविक ही हैं, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, इस पीढ़ी परिवर्तन के खिलाफ हैं और कांग्रेस के 37 विधायकों में से तीस पर हुड्डा का नियंत्रण है और यह ही स्थिति लोकसभा सदस्यों की है। हरियाणा के पाँच सांसदों में से चार हुड्डा कैम्प के हैं और इस कारण वेणुगोपाल की पीढ़ी परिवर्तन की योजना आसानी से क्रियान्वित होती नज़र नहीं आ रही है।

■ पर, वेणुगोपाल भी हार नहीं मान रहे हैं तथा सुरजेवाला को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के प्रयास उन्होंने छोड़े नहीं हैं।

■ पीढ़ी परिवर्तन के अलावा वे सुरजेवाला को कर्नाटक से हरियाणा इसलिए भी लाना चाहते हैं कि कर्नाटक एक धनाढ्य प्रदेश है, सुरजेवाला को वहाँ से हटाकर, वे अपने आदमी को कर्नाटक में प्रभारी नियुक्त करना चाहते हैं। जैसा कि विदित ही है, सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं।

■ हुड्डा ने भी परोक्ष रूप से धमकी दे रखी है कि उन पर ज्यादा दबाव डाला गया, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिये, तो वे पार्टी में विभाजन करा देंगे।

दूसरी ओर ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन्हें कर्नाटक से हटाना चाहते हैं, जो देश के सर्वाधिक सम्पन्न राज्यों में से एक है तथा उस पद पर वे अपने किसी खास व्यक्ति को लाना चाहते हैं।

सुरजेवाला ए.आई.सी.सी.

महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी हैं। हुड्डा, परिवर्तन की इस माँग पर विचार करने के राजी नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि हुड्डा ने यह संकेत दे दिया है कि अगर उन पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वे पार्टी तोड़ने पर

विचार करेंगे। यही कारण है कि विधानसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस हरियाणा में पार्टी पदाधिकारी तथा पी.सी.सी. अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भाजपा से हार गई थी।

पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत दी

पुणे, 10 जनवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के को बड़ी राहत मिली है। पुणे की विशेष अदालत ने वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। राहुल गांधी पुणे की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। वीर सावरकर के ग्रेड

■ राहुल गांधी ने, ब्रिटेन में सावरकर के हिंदुत्व पर जो बयान दिया था उस पर सावरकर के पोते ने उन पर मानहानि का केस लगाया था।

नेप्पू ने साल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर पर दिए एक बयान को लेकर मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वीर सावरकर के हिंदुत्व को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में, उन्होंने सावरकर के हिंदुत्व पर टिप्पणी की थी और कहा था कि वे बार में सावरकर ने कितना भी लिखा है। लेकिन सावरकर के परिवार के मुताबिक, जो बात राहुल गांधी ने कही थी, गलत थी। इसके बाद सावरकर के ग्रेड नेप्पू साल्टिका सावरकर ने पुणे की एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया

भाजपा का कहना है कि केजरीवाल ने भाजपा पर फर्जी वोटर लाने का झूठा आरोप लगाया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 जनवरी। भाजपा की दिल्ली इकाई ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वह विधानसभा चुनावों से पहले कथित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित झूठे दावे कर रही है।

विरोध प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोग आप प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ नारावाली तस्त्रियाँ लिये हुये थे। इनमें से कुछ लोग केजरीवाल के आवास के पास सुरक्षा बैरिकेडिंग का अतिक्रमण करने को कोशिश करते हुये दिखाई दिये।

प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा व्यवस्था का अतिक्रमण करने से रोकने के लिये पुलिस ने वॉटर केनन का

■ प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के आवास के पास लगे बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, पुलिस ने वॉटर केनन से उन्हें रोका।

■ केजरीवाल ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है कि 15 दिसम्बर से 8 जनवरी के बीच तेरह हजार नए वोटर जुड़े हैं। भाजपा यू.पी. और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रही है।

प्रयोग किया।

चुनाव आयोग को की गई विधिवत् शिकायत में, केजरीवाल ने 15 दिसम्बर से 8 जनवरी के बीच 13,000 नये मतदाता के आवेदनों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद, मीडिया को संबोधित करते हुये, केजरीवाल ने कहा, "इनमें से

बहुत सारे वोटर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से लाये गये हैं, ताकि काली वोटर रजिस्ट्रेशन किये जायें। यह गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया को क्षति पहुँचाने वाली है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के लिये चुनाव 5 फरवरी को होगा तथा 8 फरवरी को मतगणना के बाद, परिणामों की घोषणा की जायेगी।

'गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट इन्टरव्यू में गुजरात कार्यकाल को याद करते हुए कहा

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री के रूप में अपने अलग-अलग कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर, जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं।

उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में, लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरे कार्यकाल में, मैं अतीत के दृष्टिकोण से सोचता था। तीसरे कार्यकाल में, मेरी सोच बदल गयी है, मेरा मनोबल ऊँचा है और मेरे सपने बड़े हो गये हैं। प्रधानमंत्री ने आज यह टिप्पणी कामथ की पॉडकास्ट श्रृंखला 'पीपल बाय डेब्यूटीएफ' में अतिथि के रूप में उपस्थित होने के दौरान की। जब उनसे

■ प्रधानमंत्री ने जीरोधा के संस्थापक निखिल कामथ के साथ हुई बातचीत में अपने लम्बे राजनीतिक जीवन के अनुभव को भी साझा किया।

■ प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की और कहा कि वे इस मिशन के तौर पर लें।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पुराने भाषणों के बारे में पूछा गया, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, मैंने कुछ असंवेदनशील तरीके से कहा था। गलतियां होती हैं। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं।

पॉडकास्ट में मोदी ने युवा लोगों के राजनीति में आने की वकालत की, इस बात पर जोर दिया कि उन्हें महत्वाकांक्षा के साथ नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ राजनीति में आना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान सरकारी योजनाओं का जनता तक शत-प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिये समाधान खोजने पर रहेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैं

2047 तक विकासत भारत के लिये सभी समस्याओं का समाधान चाहता हूँ। सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत डिलीवरी होनी चाहिये। यही वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। इसके पीछे प्रेरक शक्ति एआई आकांक्षी भारत है।

सार्वजनिक जीवन की व्यापक चुनौतियों की चर्चा करते हुये मोदी ने स्वीकार किया कि असहमति हर क्षेत्र में आम है, चाहे वह परिवार हो, कार्यस्थल हो या राजनीति। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में संवेदनशीलता के महत्व पर जोर देते हुये कहा कि सहानुभूति के बिना कोई वास्तव में दूसरों के कल्याण के लिये काम नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा में शिक्षा पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में देने के मामले में शिक्षा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। पद्म मेहता नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़

■ अदालत में पेश याचिका में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिलवाने की माँग की है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह प्रावधान है कि बच्चों को, जहां तक संभव हो, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये क्या कर रही है पुलिस?'

हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर इन मामलों की जाँच कर रहे अधिकारी को उपस्थित रहने के आदेश दिये

जयपुर, 10 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री रोकने के उपायों पर असंतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस मुख्यालय को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि ई-सिगरेट की बिक्री से संबंधित ऑन लाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस (सी.जे.) एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताका प्रियांशा गुप्ता ने 2022 में यह मामला दर्ज किया था, तब वे खुद लॉ के चौथे वर्ष की छात्रा थीं, अब वे अधिवक्ता हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि केन्द्र सरकार ने साल 2019 में कानून लाकर ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, बेचान और वितरण पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद, प्रदेश में ई-सिगरेट आसानी से मिल रही है। कई जगह नाबालिग खुले आम इसका

■ याचिकाकर्ता प्रियांशा गुप्ता, जिसने 2022 में यह मामला दर्ज किया था और जब वो खुद वकालत पढ़ रही थीं और चौथे वर्ष की छात्रा थीं, ने कम-से-कम 13 वैबसाइटों का ब्योरा दिया है, जहां ऑनलाइन ई-सिगरेट बिक रही हैं।

■ इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कई आर.टी.आई. लगाई, यह जानने के लिये कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितनी शिकायतें व एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, कितने चालान पेश किये हैं इत्यादि। परंतु पुलिस प्रशासन ने इसका कोई भी ब्योरा नहीं दिया और कहा कि वे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इससे जाहिर होता है पुलिस ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

सेवन करते नजर आते हैं, जिससे साबित है कि राज्य सरकार कानून के क्रियान्वयन में फेल हो गई है। याचिका में गुहार की गई कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 के नियम कायदों के अनुसार भी, किसी भी

वस्तु या खाद्य पदार्थ में तम्बाकू या निकोटिन का प्रयोग वर्जित है। पर ऑनलाइन ई-सिगरेट की बिक्री हो रही है और राज्य और पुलिस प्रशासन इसे रोकने में विफल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह व्यापार इतना व्यवस्थित है कि गुगल पर ई-सिगरेट टाइट करने से ही एसे कई वेबसाइट सामने आ जाती हैं, जो ऑनलाइन सिगरेट बेच रही होती हैं।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एसी 13 वेबसाइटों का ब्योरा भी दिया है, जो वर्तमान में कार्यरत हैं और ई-सिगरेट बेच रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई पान की दुकानों पर भी ई-सिगरेट मिलती हैं।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि 2019 में ई-सिगरेट की बिक्री पर बैन लगने के बाद, आर.टी.आई. के तहत यह जानकारी इकट्ठी करनी चाही कि, पहला : 2019 के बाद अभी तक राजस्थान में इस मामले पर कितने मुकदमें दर्ज किये हैं, दूसरा : इस मामले पर कितनी शिकायतें और एफ.आई.आर. और कितने चालान पेश हुए हैं, तीसरा : इस अपराध जुड़े मामलों में कितने लोगों पर मामले अदालतों में चल रहे हैं, कितने लोग दोषी करार दिये जा चुके हैं और कितने लोग बरी कर दिये गये हैं, चौथा : 2019 के कानून को लागू करने के लिये प्रदेश में क्या नियम कायदे और नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति जिन्हें औपचारिक सजा सुनाई गई

नई दिल्ली, 10 जनवरी। अमेरिका की मेनहटन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हर्ष मनी केस में बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। दोषी होने के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप जेल और जुर्माना दोनों से बच गए।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

■ पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए पैसे देने के मामले में अदालत ने ट्रम्प को दोषी माना, किन्तु कोई सजा नहीं दी और बिना शर्त रिहा कर दिया।

को हर्ष मनी मामले में शुक्रवार को औपचारिक रूप से सजा सुनाई गई, हालांकि न्यायाधीश ने कोई भी सजा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ट्रंप अब जेल की सजा या जुर्माने के डर से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अश्विन अब अपना क्रिकेटिंग करियर खत्म होने पर, तमिलनाडु की राजनीतिक पिच पर "बोलिंग" करेंगे?

चेन्नई में एक जाने-माने प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए "हिन्दी भाषा" पर सारगर्भित टिप्पणी कर राजनीतिक हल्कों में तहलका मचा दिया

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। क्रिकेटर आर. अश्विन, जिन्होंने हाल ही में टैस्ट क्रिकेट से सन्यास की घोषणा की है, ने राजनीतिक पिच पर एक अलग ही गुगली फेंकी और हिंदी भाषा की स्थिति पर अपना निजी तथ्यात्मक आँकड़वर्षन रखा।

सवाल यह है कि क्या अश्विन राज्य में राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। शायद नहीं, क्योंकि उनके करीबी लोगों ने इससे इन्कार किया है, पर हिंदी पर उनकी अप्रत्याशित टिप्पणी ने राजनैतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

अश्विन की इस टिप्पणी ने कई हिंदी समर्थकों को भी आकर्षित किया है, जो हिंदी को राष्ट्र भाषा मानते हैं, पर सच्चाई यह है कि भारत में कोई राष्ट्र भाषा है ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन करते समय यह पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट उनसे हिंदी में सवाल पूछना चाहता है, फिर उन्होंने यही सवाल अंग्रेजी के लिए पूछा। दोनों बार पूरे कक्ष में शांति रही, फिर उन्होंने तमिल के लिए पूछा तो सभी ने एक साथ हॉं में जवाब दिया। अपना भाषण शुरू करने से पहले अश्विन ने जानबूझकर यह चाल खेली। उन्होंने घोषणा की कि हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है। हिंदी के उल्लेख पर छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर वे बोले, मुझे लगता है कि मुझे यह कहना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है, यह सरकारी भाषा है। हिंदी पर अश्विन की टिप्पणी से बहस छिड़ गई है।

तमिलनाडु, जहां 60 के दशक में भाषा विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी थी, तब भारी आंदोलन शुरू हुआ।

क्रिकेटर अश्विन ने शुक्रवार को चेन्नई के एक प्राइवेट कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय यह पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट उनसे हिंदी में सवाल पूछना चाहता है, फिर उन्होंने यही सवाल अंग्रेजी के लिए पूछा। दोनों बार पूरे कक्ष में शांति रही, फिर उन्होंने तमिल के लिए पूछा तो सभी ने एक साथ हॉं में जवाब दिया।

अपना भाषण शुरू करने से पहले अश्विन ने जानबूझकर यह चाल खेली। उन्होंने घोषणा की कि हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है। हिंदी के उल्लेख पर छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर वे बोले, मुझे लगता है कि मुझे यह कहना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है, यह सरकारी भाषा है। हिंदी पर अश्विन की टिप्पणी से बहस छिड़ गई है।

तमिलनाडु, जहां 60 के दशक में भाषा विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी थी, तब भारी आंदोलन शुरू हुआ।

उन्हें अंततः गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों, के दबाव के आगे झुकना पड़ा।

उन्होंने अपने भाषण से पहले श्रोताओं से पूछा, क्या आप मुझसे हिन्दी में सवाल पूछना चाहते हो?

श्रोताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पुनः अश्विन ने फिर पूछा, "तो क्या आप मुझसे अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे?" फिर भी श्रोताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अश्विन ने फिर पूछा, "क्या आप तमिल में मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब चाहेंगे?", श्रोता, यह सुनकर झूम उठे।

जनता का मूड भांपकर अश्विन ने तमिल में अपना भाषण दिया।

भाषण के बाद, अश्विन ने सारगर्भित टिप्पणी की, "हिन्दी राष्ट्रीय भाषा नहीं, केवल ऑफिशियल भाषा है, कुछ सरकारी काम करने की भाषा है।"

जैसा कि विदित ही है, "हिन्दी भाषा" दक्षिण भारत में एक भारी उत्तेजना व राजनीति का मुद्दा है।

1960 के हिन्दी विरोधी आंदोलनों के कारण, कांग्रेस पर आरोप लगा कि कांग्रेस हिन्दी थोपने का प्रयास कर रही है, अंततोगत्वा कांग्रेस सरकार गिरी और उसके बाद आज तक तमिलनाडु में सत्ता में नहीं आ पाई है।

दक्षिणी राज्यों, के दबाव के आगे झुकना पड़ा।

गौशाला में जब भी गौ दान किया है मेरे को लाभ ही प्राप्त होता है : तोदी

राजलदेसर । राजलदेसर कस्बे के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्री राजलदेसर गौशाला के संरक्षक ईश्वर चंद तोदी एवं उनकी धर्मपत्नी शांति देवी तोदी ने श्री राजलदेसर गौशाला में मलमास के दौरान पांच गौ माता का गौ दान करने का संकल्प लिया था जिसके तहत शुक्रवार को द्वितीय चरण के दौरान उन्होंने दो गौ माता का विधि विधान से पंडित बृजेश दाधीच ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके गौ दान किया एवं देश में खुशहाली की कामना की ।

साथ ही उन्होंने कहा मैं जब भी श्री राजलदेसर गौशाला में गौ दान करता हूँ तो मेरे को जयपुर पहुंचते ही लाभ ही प्राप्त होता है एवं नए उद्योग में आयाम स्थापित होते हैं उन्होंने कहा कि गौ दान

अधिक से अधिक करना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है साक्षात् गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है ।

उन्होंने सभी गौ भक्तों से भामाशाहों से आग्रह किया कि श्री राजलदेसर गौशाला में आकर गौ दान अवश्य करें ताकि आपका भी भाग्य चमकता रहे । साथ ही उन्होंने श्री राजलदेसर गौशाला का भ्रमण किया भ्रमण के दौरान गौशाला में बने गौ भक्तों के सहयोग से भामाशाह के सहयोग से सबसे बड़ा निर्मित गौ आवास गृह का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा सभी गौ भक्तों के प्रयास से इतना भव्य गौ आवास गृह जो बना है वह सभी गौ भक्तों की मेहनत का

फल है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है । साथ ही उन्होंने बारिश के पानी के स्टोरेज के बारे में चर्चा की । चर्चा के दौरान गौशाला के मंत्री ललित दाधीच ने 10 पानी के स्टोरेज बनाने के लिए उनके पास प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा पीने का पानी अमृत के समान होता है गौ माता को बरसाती पानी अगर मिलता है तो बहुत ही पुण्य का कार्य है उन्होंने अपनी ओर से एक पानी का स्टोरेज बनाने की तुरंत ही घोषणा की एवं अन्य दानदाता एवं अनेकों भक्तों को भी अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा क्योंकि जल ही जीवन है जल के बिना मनुष्य अधूरा है जीव जंतु का जीना ही दुर्लभ है साथ ही उन्होंने अंधी विकलांग गौ माता को अपने हाथों से

गुड़ खिलाया इसके अलावा गौशाला के बारे में भी उन्होंने चर्चा की एवं अपनी ओर से जो भी सहयोग होगा हमेशा सहयोग करने कि बात कही । इस अवसर पर गौशाला के मंत्री ललित दाधीच ने गौशाला की पूरी जानकारी दी एवं भविष्य की योजना के बारे में बताया इस अवसर पर पशु चिकित्सा प्रवाही डॉक्टर हीरालाल सोनी, गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगतमल पाण्डिया, हनुमानमल सोनी, परमेश्वर फोगला, मुकेश श्रीमाल विनोद भाटिया, रतनलाल बारपाल, अनिल तोदी, मदन दाधीच, मांगीलाल प्रजापत, मैनेजर राधेश्याम पांडे, विशाल प्रजापत, नंदकिशोर पांडे आदि गौशाला के कर्मचारी उपस्थित रहे ।

डी.आई.जी. बनने पर किया सम्मान

झुंझुनू । एसपी शरद चौधरी का हाल ही में डीआईजी के पद पर प्रमोशन हुआ है। जिसके बाद शुक्रवार को झुंझुनू में उनका विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मान किया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने शरद चौधरी के प्रमोशन पर उनका सम्मान किया। इस मौके पर शरद चौधरी ने कहा कि उनका झुंझुनू का कार्यकाल छोटा रहा है। लेकिन उन्हें झुंझुनू की याद हमेशा रहेगी। यहां के लोगों ने पुलिस का खूब सहयोग किया है। जिसके चलते हर अपराध को रोकने में और अपराधों के राजफाश में मदद मिली। उन्होंने कहा कि डीआईजी बनने के बाद अब उनका तबादला होगा। लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वे झुंझुनू छोड़कर जाएं। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष संपत चुड़ैलवाला, सुनील पाटोदिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदीप पाटोदिया, श्री गोपाल गौशाला अध्यक्ष प्रमोद खंडेलिया, मंत्री नेमी अग्रवाल, श्री गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष आनंद टीबड़ा, श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था के टुस्टी डॉक्टर दीपन तुलस्यान, सुनील तुलस्यान, लॉयंस क्लब झुंझुनू के रघुनाथ पोद्दार, वस्त्र व्यवसायी राजेश देहिया एवं संजय नांगलिया आदि ने शरद चौधरी का दुपट्टा, साफा एवं शॉल ओढ़कर माल्यार्पण के साथ स्वागत अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि आईपीएस शरद चौधरी मुद्दु भाषी, मिलनसार स्वभाव के धनी मूलतः कानपुर निवासी हैं।

नीमकाथाना जिला हटाये जाने पर सर्व समाज का विरोध जारी

पाटन । नीमकाथाना जिला को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर सर्व समाज का विरोध देखने को मिल रहा है वहीं अनेकों समाज के लोग आंदोलनकारियों को समर्थन दे रहे हैं। ग्यारहवें दिन भी भूख हड़ताल जारी रही, जहां बनवारी सैनी डेहरा जोहड़ी, दुर्गा प्रसाद सैनी डेहरा जोहड़ी, अमरचन्द सैनी डेहरा जोहड़ी, भाग्यराम सैनी पूर्व सरपंच डेहरा जोहड़ी, प्रभात गुर्जर राणासर, रोशन लाका भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल पर बैठने वाले लोगों को विधायक सुरेश मोदी ने माला पहनाई। इन सभी लोगों ने नीमकाथाना जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ कर धरने को जारी रखा।

नीमकाथाना जिला बचाने के लिए :-शुक्रवार को माली-सैनी समाज विकास संस्थान और युवा शक्ति मंच ने पुराना बस स्टैंड से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय तक बाइक रैली निकाल कर आक्रोश जताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को समर्थन दिया।

नीमकाथाना जिला हटाने से राजस्थान सरकार के खिलाफ धीरे धीरे लोगो में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। शहर में जगह-जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया

जागरूकता शिविर आयोजित

सीकर । महावीर इन्टरनेशनल एवं वीरा केंद्र सीकर के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुनील ढण्ड द्वारा मधुमेह जागरूकता शिविर का आयोजन दीवान जी की धर्मशाला जाटिया बाजार में किया गया। जिसमें डॉ. सुनील ढण्ड द्वारा आये हुए सदस्यों एवं समाज के गणमान्य लोगों को मधुमेह रोग के बारे में जानकारी दी, बताया कि किस प्रकार से इस रोग को लेकर लोगों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनेकों भ्रांतियां हैं। डॉ. ढण्ड ने लोगों की भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि किस प्रकार से हम खानपान और अपने जीवनशैली में बदलाव कर मधुमेह और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। शिविर संयोजिका वीरा नीलम मिश्रा द्वारा डॉ. सुनील ढण्ड को (पौधा) देकर सम्मानित किया। संस्था अध्यक्ष वीर सुभाष मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार समाज और देश में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियाँ आम आदमी को अपनी चपेट में ले रही हैं, उससे बचने के लिए इस प्रकार के जागरूकता शिविर निरंतर रूप से लगाना आवश्यक है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महावीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। शिविर में वीरा सन् मोदी सचिव राजेंद्र पहाड़िया, वरिष्ठ सदस्य डॉ. एम. पी. जैन, महेश शर्मा, शिवकुमार जांगिड़, संगीता पहाड़िया सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया।





एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ



हर चौथे माह में अंतरा इन्जेक्शन लगावाएं अनचाहे गर्भ ठहरने की चिंता से मुक्ति पाएं

बच्चों में अंतर रखने का आसान व सुरक्षित...

अंतरा

— एम.पी.ए. इंजेक्शन —

प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (PPIUCD)

लाखों महिलाओं ने अपनाई

आप भी अपनाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता से मुक्ति पाएं

- ▶ प्रसव के बाद 48 घंटों में प्रशिक्षित चिकित्सक/कर्मियों से PPIUCD लगवाएं
- ▶ पुनः गर्भधारण चाहने पर आसानी से निकलवाएं
- ▶ बच्चों में अंतर रखने का सरल व सुरक्षित गर्भनिरोधक साधन

तीन महीने के अंतराल पर स्वास्थ्यकर्मी से एक इंजेक्शन लगावाएं जब गर्भधारण चाहें, अंतरा लगवाना बंद कर दें।

सभी राजकीय जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी व स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन साधनों की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए एएनएम/आशा सहयोगिनी से सम्पर्क करें।

साधन-परामर्श हमारा : चयन-फैसला आपका



गर्भ निरोधक गोमियाँ छाया / माला-एन



कंडोम



आईयूसीडी 375, 380 ए



इंजेक्शन अंतरा एमपीए



इंजी पिल



पुरुष नसबंदी (हर माह तैयार हुवाकर बदलें/दोहराएं)



महिला नसबंदी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईईसी) राजस्थान, जयपुर






श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

13 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र का वितरण **एवं** **31 हजार करोड़ रुपए के 76 हजार से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास**

राज्य स्तरीय समारोह

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

विशिष्ट अतिथि
सुश्री दिया कुमारी माननीया उप मुख्यमंत्री
श्री जोगाराम पटेल माननीय संसदीय कार्यमंत्री

12 जनवरी, 2025

प्रातः 11:00 बजे

बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर

निर्भाई जिम्मेदारी - हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर रिफाइनरी कार्मिकों में उत्साह दिखा

श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई

बालोतरा, 10 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बालोतरा जिले में पंचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया एवं समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार एवं रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस में बैठ कर रिफाइनरी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में इयूल फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस यूनिट के निर्माण में बुजुर्ग खलीफा से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंचपदरा में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ बातचीत भी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इयूल फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। जिसमें बुजुर्ग खलीफा से भी अधिक कंक्रीट का उपयोग हुआ है। रिफाइनरी के एक तिहाई श्रमिक (लगभग नौ हजार) इसी यूनिट में काम करते हैं।

भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी व इसके आस-पास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिये एच.आर.आर.एल. के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये।

रिफाइनरी परिसर में मुख्यमंत्री ने हाईटेशन मोटर के जरिए कम्प्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के समीप सांभरा ग्राम में एच.आर.आर.एल. द्वारा ईएससी फंड के माध्यम से बनाए जा रहे स्कूल एवं अस्पताल को शीघ्र शुरू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को

अधिक कंक्रीट का उपयोग हुआ है। यह रिफाइनरी का सबसे बड़ा प्लांट भी है, जहाँ, रिफाइनरी के एक तिहाई श्रमिक (लगभग 9 हजार) काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कोक डोम और ट्रीटिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान शर्मा ने श्रमिकों के साथ बातचीत की तथा उनके साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण

कार्यों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिफाइनरी और आस-पास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभाव कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को एक विशेषाधिकारी नियुक्त

करने के निर्देश दिए, जो कि 15 दिन में रिफाइनरी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट बनाए।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के मॉडल का अवलोकन भी किया और रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्वा, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल, प्रियंका चौधरी, अरूण चौधरी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताम शर्मा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत, रीको प्रबन्ध निदेशक इन्द्रजीत सिंह, एच.आर.आर.एल. के निदेशक एस. भारतन, सीओ कमलाकर आर विखर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

‘मस्जिद के समीप के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखें’

■ सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाहीजामा मस्जिद के कुएं पर नगर पालिका के नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है।

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर, विवादित संभल मस्जिद के पास के कुएं का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय नगर पालिका को नोटिस को 21 फरवरी, 2025 तक लागू नहीं करने और दो सप्ताह में स्थिति का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने संभल नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे पोस्टरों के माध्यम से जारी किए गए अपने सार्वजनिक नोटिस को लागू न करें, जिसमें शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया गया है तथा वह श्रद्धालुओं की पूजा व स्नान के लिए बनाया गया था।

श्री अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि उस जगह के आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्नान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहा गया है।

पीठ ने कहा कि यदि दूसरा पक्ष भी कुएं का उपयोग करता है तो कोई नुकसान नहीं है। यूपी सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है, पर मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि कुएं का आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर है, लेकिन राज्य सरकार पक्षपातपूर्ण रुख अपना रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मातृ भाषा में शिक्षा मिलने के कारण सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालों के अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।

दिल्ली के बाकी प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा की बैठक

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की शुक्रवार देर शाम यहां पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई गयी, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिये जाने की उम्मीद है। पार्टी दिल्ली की 70 विधान सभा सीटों में से 29 के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नयी विधान सभा के चुनाव की गजट अधिसूचना आज जारी हो चुकी है और नामांकन 17 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे। भाजपा सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री

■ मोदी, अमित शाह, राजनाथ व नड्डा भी बैठक में शामिल हुए।

राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। भाजपा द्वारा अब तक घोषित 29 प्रत्याशियों में बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का भी नाम है। पार्टी ने वर्मा को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उतारा है।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



राजस्थान सरकार



एक वर्ष
परिणाम उत्कर्ष



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



प्रदेश के किसान बन रहे अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता



राजस्थान को पी.एम. कुसुम योजना के घटक-ए में 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन के लिए

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

एवं

श्री प्रह्लाद जोशी
माननीय केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

एवं

का

हार्दिक आभार

किसानों को वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ते कदम

घटक-ए व सी में आवंटित 12,000+ मेगावाट में से 5,247 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के अवार्ड जारी

2,838 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद अनुबंध संपादित

अब तक 405 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित, प्रत्येक जिले में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र

2,138 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की निविदा प्रक्रियाधीन, 5000 मेगावाट के लिए शीघ्र जारी होंगी निविदा

निभाई जिम्मेदारी - हर घर खुशहाली

ऊर्जा विभाग, राजस्थान

‘ई-सिगरेट की बिक्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसे हैरानी हुई कि राजस्थान सरकार की क्राइम ब्रांच ने इन सबालों के जवाब देने के लिये कोई भी रिपोर्ट बरकरार नहीं रखा है, इससे साबित होता है कि राज्य सरकार इससे बेपरवाह है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में कई दस्तावेज रिपोर्ट पर हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार को बार-बार कहा गया कि ई-सिगरेट रोकने के लिये कार्रवाही करें, लेकिन इसे रोकने के लिये केवल कागजी कार्रवाही की गई है। अदालत ने कहा कि कम्प्यूटर्स के 2022 में दायर शपथ पत्र से ये ही जाहिर होता है कि ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये विभाग कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस विभाग की अपनी सीमाएं हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि शपथ पत्र दायर किये काफी समय हो गया है, उन्हें नया शपथ पत्र पेश करना होगा। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर जो अफसर ई-सिगरेट की बिक्री को मॉनिटर करने के लिये नियुक्त किये जायें, वे वी.सी. के जरिये अदालत में उपस्थित रहें। इस मामले में अगली तारीख 1 फरवरी 2025 तय की गई है।

अश्विन अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जाने गंवाई। पुराने लोग याद करते हैं कि तब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, हिंदी सम्बंधी फैसले ने राज्य में कांग्रेस को खलनायक बना दिया और उसके बाद ड्रिड पार्टी सत्तारूढ़ हुई और तब से लेकर आज तक कांग्रेस अपने दम पर राज्य में पुनः सत्ता में नहीं आ पाई है।

कांग्रेस को राज्य में किसी न किसी ड्रिड पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है, कभी द्रमुक से, तो कभी अनाद्रमुक से। फिलहाल दो दशक से कांग्रेस का द्रमुक से गठबंधन है।

अश्विन की टिप्पणी से तमिलनाडु में उनके प्रशंसक अवश्य बढ़ गए होंगे।

कड़ाके की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विलंबित हैं और 26 ट्रेन अपने निर्धारित समयसे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समयानुसार तड़के साढ़े चार बजे से पालम में दृश्यता शून्य है।

मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के अनेक इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान बताया है।

इस बीच राज्य के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 11 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।

ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुक्त होकर व्हाइट हाउस जा सकेंगे।

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में दोषी करार दिया गया था। ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान या पूर्व) हैं, जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रम्प को ओर से कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ, मेनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में सजा सुनाने का रास्ता खुल गया था।

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें सजा सुनाया जाना एक ऐसा आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करता है, जिसका गवाह अमेरिका पहले नहीं है। कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की विशाल शक्तियों और देश के कानूनों और संविधान के अंतिम संरक्षक बनने वाले हैं।